EDUZONE: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal (EIPRMJ), ISSN: 2319-5045
Volume 2, Issue 2, July-December, 2013, Available online at: www.eduzonejournal.com

स्नातक शिक्षा के मुद्दे एवं सरोकार

सोनिया

Bachelor in Education, Haryana Institute of Education, Bahadurgarh

सार

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बडा उच्च शिक्षा तंत्र है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में महाविद्यालयों एव ं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विगत 70 वर्षों में आजादी के बाद देश के विश्वविद्यालयों की संख्या में 40 गुना, महाविद्यालयों में 80 गुना, विद्यार्थियों की संख्या में 80 गुना और शिक्षकों की संख्या में 30 गुना वृद्धि हुई है। विकसित देशों में कम संस्थानों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाता है और एक ही संस्थान में हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि भारत में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के बिना भी हजारों कॉलेज चल रहे हैं ।

बीज शब्द : शिक्षा , उच्च शिक्षाप्रणाली, गुणवत्ता, मुद्दे ।

परिचय

ऐसी शिक्षा का स्वरूप विशदता के साथ भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हुआ था। उच्च शिक्षा देनेवाले भारतीय गुरुकुलों की बड़ी विशेषता यह थी कि उनमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा शिष्याध्यापक प्रणाली (मोनीटोरियल सिस्टम) से दी जाती थी। सबसे ऊपर के छात्र अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को पढ़ाते थे और वे अपने से नीचे वाले को। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पुत्र ही भर्ती किए जाते थे और वर्णों के अनुकूल ही बालकों को शिक्षा भी दी जाती थी तथापि नित्यधर्म, स्वच्छता, शील और शिष्टाचार की शिक्षा प्रत्येक छात्र को दी जाती थी और प्रत्येक छात्र को गुरुकुल में रहकर आश्रम का समस्त कार्य स्वयं करना पड़ता था। कुछ गुरुकुल तो इतने बड़े थे कि वहाँ एक एक कुलपति, दस सहस्र ऋषियों और ब्रह्मचारियों का अन्य दानादि देकर उनको पढ़ाने का प्रबंध करते थे और छात्र भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुदक्षिणा देते थे किंतु कोई भी राजा इन गुरुकुलों के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करता था। इन गुरुकुलों का प्रारंभ वास्तव में उन परिषदों से हुआ जिनमें चार से लेकर 21 तक विद्वान् और मनीषी किसी नैतिक सामाजिक या धार्मिक समस्या पर व्यवस्था देने के लिये एकत्र होते थे। कुछ गुरुकुलों ने वर्तमान सावास विश्वविद्यालय (रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी) का रूप धारण कर लिया था। इन गुरुकुलों में वेद, वेदांग, दर्शन, नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दंडनीति, सैन्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद और आयुर्वेद आदि सभी विषयों की उच्चतम शिक्षा दी जाती थी और जब छात्र, सब विद्याओं में पूर्ण निष्णात हो जाता था तभी वह स्नातक हो पाता था। ब्राह्मणों को यह छूट थी कि वे चाहें तो जीवन भर विद्यार्जन करते रहें।

योरप में मिस्र की सभ्यता सर्वप्राचीन मानी जाती है किंतु वहाँ की उच्च शिक्षाप्रणाली का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। बाबुल, असुरिया (असीरिया) के निवासियों तथा हिब्रू और फिनीसी लोगों मे राजशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और भूगोल की उच्च शिक्षा गिने चुने लोगों को ही दी जाती थी। यूनान में सौंदर्य की उदात्त भावना के साथ व्याकरण, काव्य, भाषा, शैली, अलंकारशास्त्र, वक्तृत्वकला, संगीत, गणित, भौतिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। एक एक व्यक्ति एक एक विषय का पंडित होता था। उसी के पास युवक शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। स्पार्ता के लोगों को केवल युद्ध की ही शिक्षा मिली, अन्य विषयों का पूर्ण अभाव रहा। वास्तव में एथेंस ही युनानी उच्च शिक्षा का विद्यानगर था जहाँ सुकरात, ज़ेनोफन, अफलातून और अरस्तू जैसे विद्वान् शिक्षाशास्त्री और दार्शनिक विद्यमान थे। जब रोमवालों ने यूनान को जीत लिया तब रोम की शिक्षाप्रणाली पर यूनान का यह प्रभाव पड़ा कि वहाँ भी इतिहास, विज्ञान, दर्शन, वक्तृत्वकला और शास्त्रार्थकला की उच्च शिक्षा दी जाने लगी जिसके प्रभाव से सिसरो, सैनेका और क्विंतिलियन जैसे शिक्षाशास्त्री और वक्ता उत्पन्न हुए तथा थोड़े ही समय में उच्च शिक्षा के अनेक विद्यालय भी खुल गए। किंतु रोम साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के साथ ही यूनान और रोम की संपूर्ण शिक्षापद्धति समाप्त हो गई।

ईसाई मठों में पहले धर्मशिक्षा और प्रार्थना के साथ पढ़ना लिखना, गाना, पूजा करना और गणित की शिक्षा दी जाती थी किंतु इसके पश्चात् वहाँ विद्यात्रयी (लातिन का व्याकरण, ज्यामिति, ज्योतिष और संगीत) का मिलाकर सात ज्ञानविस्तारक कलाओं के शिक्षण का क्रम चला और तभी से इन शास्त्रों के लिये (आर्ट) शब्द का प्रयोग चल पड़ा जो आजकल भ्रामक रूप से हमारे विश्वविद्यालयों की उपाधि में प्रयुक्त हो रहा है। योरप में प्रारंभ में कुछ विद्यार्थी किसी विशेष विद्या के आचार्य के पास अध्ययन के लिये एकत्र होते थे जैसे पैरिस में धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिये, सालेरनो में भैषज्यविद्या के लिये या बोलोना में न्यायनीति (कानून) सीखने के लिये। इस प्रकार दक्षिण योरप में बोलोना के आदर्श पर विश्वविद्यालय खुले और उत्तर में पैरिस के आदर्श पर। इनके अतिरिक्त एक शिक्षाचार्य (बैकेलौरिएट) का प्रमाणपत्र भी था जो शिक्षक होने के लिये अनुज्ञापत्र समझा जाता था। धीरे धीरे विश्वविद्यालयों ने वर्तमान रूप धरण किया। इनमें उच्चतम शिक्षा का अर्थ है हाई स्कूल के पश्चात् महाविद्यालयों (कालेजों) या व्यावसायिक संस्थाओं (ट्रेनिंग कालेज, मेडीकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेज, टेक्निकल कालेज, कला महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, न्यायनीति (लॉ), कृषि, वाणिज्य महाविद्यालय आदि) में दी जानेवाली शिक्षा जिसके लिये विश्वविद्यालय से उपाधि या राजकीय विभागों की ओर से परीक्षा लेकर प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा देने का अधिकांश कार्य विश्वविद्यालय ही करते हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commision of India -HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान NEP-2010 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपा नु त' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2012) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। NEP-2014 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रर्य म में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूनु प डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों अं या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरसुक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंकबैं ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शनर्श के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रर्यम को समाप्त कर दिया गया।

उच्च शिक्षा के साथ मुद्दे

शिक्षण गुणवत्ता

पहला मुद्दा है कि भारत में उच्च शिक्षा का सामना करना पड़ रहा है शिक्षण की गुणवत्ता में कमी आई है। शिक्षकों को नौकरी के लिए प्रशिक्षित और योग्य नहीं हैं जिन्हें वे सौंपा गया है। कुछ कॉलेज युवा स्नातकों को ऐसे प्रोफेसरों के रूप में भर्ती करते हैं जिनके पास कोई अनुभव या ज्ञान नहीं है। तो यह एक बड़ी समस्या है।

फाइनेंसिंग

वित्त पोषण भारत में उच्च शिक्षा के साथ भी एक मुद्दा है। हां भारत पहले से ही उच्च शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च कर रहा है और यह और अधिक खर्च नहीं कर सकता है। हालांकि यदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना है तो अधिक वित्तपोषण की आवश्यकता है।

निजीकरण

निजीकरण भी एक बड़ी समस्या है कि उच्च शिक्षा का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा का निजीकरण जाने का रास्ता है। हालांकि सिर्फ निजीकरण समस्या को हल करने वाला नहीं है। आपको युवा छात्रों में रचनात्मकता , कल्पना और नए कौशल सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा।

कोटा प्रणाली

बहस कोटा प्रणाली बहुत विवादास्पद है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो मुझे आपको बताना होगा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कोटा अच्छा नहीं है। प्रतिभा और योग्यता आपकी पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि कोटा प्रणाली अभी भी एक चुनौती है।

राजनीतिक फैक्टर

राजनीतिक प्रभाव भी एक बुरी चीज है और उच्च शिक्षा के साथ एक मुद्दा है। शासी निकाय अपने मामलों में कोई राजनीतिक प्रभाव या हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं।

नैतिक मुद्दे

युवा पीढ़ी को अपने देश की सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे सिर्फ नौकरी और भारी वेतन पैकेज लेने में अधिक रुचि रखते हैं।

उच्च शिक्षा के साथ समस्याएं

हम उन गंभीर चुनौतियों के बारे में बहस करेंगे जिन पर उच्च शिक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

आपूर्ति और मांग में गैप

भारत की सकल नामांकन दर (जीईआर) सिर्फ 19% है जो अच्छी नहीं है। जीईआर विश्व औसत से 6% कम है और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित दुनिया की तुलना में कम से कम 50% कम है। अगर हमें भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार करना है तो इसे बदलना होगा।

कम गुणवत्ता वाले संस्थानों का मशरूम

पूरे देश में कम गुणवत्ता वाले संस्थानों की मशरूम उच्च शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। इन नए कॉलेजों में क्षमता की कमी है और वे सभी छात्रों और उनके माता-पिता से पैसे कमाने के बारे में हैं। बहुत अधिक ग्लैमर और शिक्षा की कम गुणवत्ता है।

कोई परियोजना आधारित शिक्षा नहीं

उच्च शिक्षा में परियोजना आधारित शिक्षा की कमी है। युवा स्नातकों को नए कौशल सीखना होगा , विशेष रूप से व्यावसायिक कौशल जो उन्हें नौकरी दे सकते हैं। इसलिए हम परियोजना आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। बस सिद्धांत पर्याप्त नहीं है, हमें व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए।

कोई रणनीति नहीं

भारत में उच्च शिक्षा के लिए कोई रणनीति नहीं है। हमारे पास देश में आने वाले विदेशी छात्र नहीं हैं और यहां पढ़ रहे हैं। सरकार के पास इसके लिए कोई योजना नहीं है और यह एक बड़ी चुनौती है।

केवल सेवा उद्योग क्यों?

हम सेवा उद्योग के साथ जुनूनी हैं। हम सभी परिसर चयन में चयन करना चाहते हैं, इसलिए हम केवल सर्विसिंग सेक्टर में नौकरियां पसंद करते हैं। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां पैदा करने की बात आती है तो उच्च शिक्षा समस्या का समाधान नहीं करती है। यह एक बड़ी समस्या है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

i. इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ज़ोर देना था।
ii. इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये **"ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड"** लॉन्च किया।
iii. इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ **'ओपन यूनिवर्सिटी'** प्रणाली का विस्तार किया।
iv. ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित **"ग्रामीण विश्वविद्यालय"** मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया।

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ

i. **राज्यों का सहयोगः** शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।
ii. **महँगी शिक्षाः** नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
iii. **शिक्षा का संस्कृतिकरणः** दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
iv. **फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होनाः** कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।
v. **वित्तपोषणः** वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6%खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।
vi. **मानव संसाधन का अभावः** वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2005 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।

निष्कर्ष

अंततः किसी भी देश के लिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा का अपना महत्व है जैसे उच्च शिक्षा का अपना महत्व है। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में उच्च शिक्षा में कई चुनौतियां और मुद्दे हैं। हमें उनके बारे में बात करने और हाइलाइट करने की आवश्यकता है ताकि सरकार ऐसे मुद्दों को हल कर सके। वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति के बारे में एक विचार प्राप्त करने के लिए आपको इस लेख को पढ़ने की जरूरत है।

संदर्भ

[1] एमएचआरडी (2011). एन ुअल रिपॉर्ट, डिर्पाटमेंट ऑफ हायर एज्युकेषन, गवरमेंट ऑफ इण्डिया,• नई दिल्ली.
[2] एमएचआरडी (1989). नेषनल पॉलिसी आन एजुकेषन•–1986, पीऑए–1990, न्यु द हलीः गवरनमेंट ऑफ इन्डिया

[3] सिंह, आर. पी. (2010). ऑन ऑपनिंग अ 'वर्ल्ड' क्लास युनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी न्यूज, नई• दिल्ली, 48 (37), सितम्बर 13–19, 2010

[4] सिंह, ज`.डी. व अन्य, (2001). विद्यालय प्रबन्ध व षिक्षा की समस्याएं, जयपुरः रिसर्च• पब्लिक`षन्स.

[5] तिलक, जन्धाला (2007). हायर एजुकेशन इन इंडिया फंडिंग एक्सेस, क्वालिटी और इक्विटी,• न्यूपा, नई दिल्ली.